

अनुदान संख्या 76 - पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
GRANT No. 76 - MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	5498,74,00		
		14715,59,00	14287,53,07	-428,05,93
पूरक	Supplementary	9216,85,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			426,13,29
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	35508,98,00		
		35509,00,00	2980,43,50	-32528,56,50
पूरक	Supplementary	2,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			32528,56,50

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः—

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head	(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"			
सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ	Secretariat - Economic Services			
मू.	O.	5190.00		
		4382.84	4190.20	-192.64
पु.	R.	-807.16		

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष Head				
मुख्य शीर्ष “2802” पेट्रोलियम	Major Head “2802” Petroleum			
मू.	O.	515640.00	1413756.42	1413756.42
पू.	S.	919654.00		
पु.	R.	-21537.58		
मुख्य शीर्ष “2852” उद्योग	Major Head “2852” Industries			
मू.	O.	29044.00	8775.45	8775.45
पु.	R.	-20268.55		

(I) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹124.00 लाख का प्रावधान पूर्णतः अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹124.00 lakhs remained wholly unutilized under one head.

(II) मुख्य शीर्ष “3451” – “सचिवालय – पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय” के अंतर्गत ₹999.80 लाख की बचत (₹5190.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बैठकों/सेमिनारों में वर्चुअल भागीदारी, स्थापना संबंधी व्यय में कमी और अर्थव्यवस्था कारणों के कारण हुई।

(II) Under Major Head “3451” - “Secretariat - Ministry of Petroleum and Natural Gas” - saving of ₹999.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5190.00 lakhs) was due to virtual participation in meetings/seminars, less establishment related expenses and economy reasons.

(III) मुख्य शीर्ष “2802” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत बचत हुई:—

(III) Under Major Head “2802” - savings occurred under the following heads:-

(का) “तेल और गैस का शोधन और विपणन” –

(A) “Refining and Marketing of Oil and Gas” -

(क) “तेल शोधन – नुमालीगढ़ रिफाइनरी विस्तार परियोजना” – ₹2450.00 लाख की बचत (₹50000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधानों में कटौती के कारण हुई।

(a) “Refining of Oil - Numaligarh Refinery Expansion Project” - saving of ₹2450.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹50000.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

- (ख) “तेल का विपणन – प्रधानमंत्री जी-वन योजना” – ₹15151.00 लाख की बचत (₹22726.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड से कम बिल प्राप्त होने के कारण हुई, जिसका कारण संवितरण शर्तों के दूसरे और तीसरे मील के पत्थर को प्राप्त न करना और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान में कमी करना था।
- (ग) “प्राकृतिक गैस पाइप लाइन की स्थापना – इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड (आईजीजीएल) उत्तर पूर्व प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड का हिस्सा” – ₹75662.00 लाख की बचत (₹180000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयोग के अधिकार (आरओयू) मुद्दों और मानसून के कारण निर्माण गतिविधियों की धीमी गति और व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण की कोई अतिरिक्त मांग नहीं होने के कारण हुई।
- (खा) “स्वायत्त निकायों को सामान्य सहायता” –
- (क) “भारतीय सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड आईएसपीआरएल (ओ एंड एम) को भुगतान” – ₹4987.58 लाख की बचत (₹20281.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वास्तविक स्टॉक के कारण बीमा प्रीमियम में कमी, नई पॉलिसियों में कम प्रीमियम और आईएसपीआरएल से कम दावे की प्राप्ति के कारण हुई।
- (ख) “भारतीय पेट्रोलियम ऊर्जा संस्थान (आईआईपीई), विशाखापत्तनम की स्थापना” – ₹7800.00 लाख रुपये की बचत (₹16800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भूमि आवंटन के न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण संस्थान द्वारा भूमि अधिग्रहण में देरी के कारण हुई।
- (IV) मुख्य शीर्ष “2852” – “इंजीनियरिंग उद्योग – परिवहन उपकरण उद्योग – भारत में पीएनजी के लिए
- (b) “Marketing of Oil - Pradhan Mantri Ji - VAN Yojana” - saving of ₹15151.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹22726.00 lakhs) was due to receipt of less bills from Hindustan Petroleum Corporation Limited and Indian Oil Corporation Limited owing to non-achievement of 2nd and 3rd milestones of disbursement conditions and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.
- (c) “Setting up of Natural Gas Pipe Line - Indradhanush Gas Grid Limited (IGGL) Part of the North East Natural Gas Pipeline Grid” - saving of ₹75662.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹180000.00 lakhs) was due to slow down of construction activities owing to Right of Use (RoU) issues, monsoon and no additional demand of Viability Gap Funding.
- (B) “General - Assistance to Autonomous Bodies” -
- (a) “Payment to Indian Strategic Petroleum Reserves Limited ISPRL (O&M)” - saving of ₹4987.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20281.00 lakhs) was due to reduction in insurance premium owing to actual stock, lower premium in new policies and receipt of less claim from ISPRL.
- (b) “Setting up of Indian Institute of Petroleum Energy (IPE), Vishakhapatnam” - saving of ₹7800.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16800.00 lakhs) was due to delay in taking over of the land by the institute owing to land allocation being under sub-judice.
- (IV) Under Major Head “2852” - “Engineering Industries - Transport Equipment Industries -

व्यापारिक पोतों की फ्लैगिंग” के अंतर्गत – ₹20268.55 लाख रुपये की बचत (₹29044.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) तेल विपणन कंपनियों से कम बिल प्राप्त होने के कारण हुई।

2. उपर्युक्त बचत का आंशिक उपयोग (₹84639.00 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधानों को बढ़ाने के लिए किया गया, जैसा कि संसद को पहले ही सूचित किया जा चुका है, जबकि दिसम्बर, 2023 में मुख्य शीर्ष “2802” – “सामान्य” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत ₹919654.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त किया गया:-

- (I) “तेल विपणन कंपनियों को सहायिकी” –
- (का) “एलपीजी के लिए डीबीटी” – ₹50993.53 लाख।
- (खा) “परियोजना प्रबंधन व्यय” – ₹3200.00 लाख।
- (गा) “बीसीपीएल/असम गैस क्रैकर्स कॉम्प्लेक्स को फीडस्टॉक सब्सिडी” – ₹17094.00 लाख।
- (II) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – एलपीजी के लिए डीबीटी” – ₹4842.64 लाख।
- (III) “आदिवासी क्षेत्र उप-योजना – एलपीजी के लिए डीबीटी” – ₹2508.83 लाख।
- (IV) “अंतर्राष्ट्रीय सहयोग – वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन” – ₹6000.00 लाख।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

Flagging of Merchant Ships for PNG in India” - saving of ₹20268.55 lakhs (against the sanctioned provision of ₹29044.00 lakhs) was due to receipt of less bills from Oil Marketing Companies.

2. The above savings were partly (₹84639.00 lakhs) utilized for augmenting the provisions by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹919654.00 lakhs in December, 2023 under Major Head “2802” - “General” - under the following heads:-

- (I) “Subsidy to Oil Marketing Companies” -
- (A) “DBT for LPG” - ₹50993.53 lakhs.
- (B) “Project Management Expenditure” - ₹3200.00 lakhs.
- (C) “Feedstock Subsidy to BCPL/Assam Gas Crackers Complex” - ₹17094.00 lakhs.
- (II) “Special Component Plan for Scheduled Castes - DBT for LPG” - ₹4842.64 lakhs.
- (III) “Tribal Area Sub-Plan - DBT for LPG” - ₹2508.83 lakhs.
- (IV) “International Cooperation - Global Biofuels Alliance” - ₹6000.00 lakhs.

3. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under following major head:-

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4802"	Major Head "4802"			
पेट्रोलियम पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Petroleum			
मू.	O.	3550800.00		
पू.	S.	1.00	297967.38	297967.38
पु.	R.	-3252833.62		..

(I) निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत ₹3550800.00 लाख का प्रावधान पूर्णतः अप्रयुक्त रहा:—

(का) “कच्चे तेल और गैस की खोज और उत्पादन – सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश – तेल विपणन कंपनियों को पूंजी सहायता” – ₹3000000.00 लाख – व्यय वित्त समिति (ईएफसी) द्वारा निधियों की कम स्वीकृति के कारण।

(खा) “कच्चे तेल का सॉवरेन स्ट्रेटिजिक भंडारण – कच्चे तेल रिजर्व के सॉवरेन स्ट्रेटिजिक भंडारण का निर्माण – भारतीय सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (आईएसपीआरएल) को भुगतान” – ₹550800.00 लाख – वैश्विक तेल बाजारों में विलय के रुझान और अन्य प्रासंगिक आर्थिक और राजकोषीय कारकों और आईएसपीआरएल चरण-II में भूमि खरीद को अंतिम रूप न देने के कारण प्रस्ताव को स्थगित करने के कारण।

4. उपर्युक्त बचत का आंशिक रूप से (₹297966.35 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए उपयोग किया गया, जैसा कि पहले ही संसद को सूचित किया जा चुका है, जबकि निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत दिसंबर, 2023 में ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त किया गया:—

(I) “तेल और गैस का शोधन और विपणन – सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश” –

(I) Provision of ₹3550800.00 lakhs remained wholly unutilized under the following heads:-

(A) “Exploration and Production of Crude Oil and Gas - Investments in Public Sector and other Undertakings - Capital Support to Oil Marketing Companies” - ₹3000000.00 lakhs - due to less approval of funds by Expenditure Finance Committee (EFC).

(B) “Sovereign Strategic Storage of Crude Oil - Creation of Sovereign Strategic Crude Oil Reserve - Payment to Indian Strategic Petroleum Reserves Limited (ISPRL)” - ₹550800.00 lakhs - due to deferment of proposal owing to merging trends in global oil markets and other relevant economic and fiscal factors and non-finalisation of land purchase in ISPRL Phase-II.

4. The above savings were partly (₹297966.35 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in December, 2023 under the following heads:-

(I) “Refining and Marketing of Oil and Gas - Investments in Public Sector and other Undertakings” -

- (का) “गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया” – ₹284048.59 लाख। (A) “Gas Authority of India” - ₹284048.59 lakhs.
- (खा) “इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड” – ₹9918.01 लाख। (B) “Engineers India Ltd.” - ₹9918.01 lakhs.
- (II) “कच्चे तेल का सॉवरेन स्ट्रेटिजिक भंडारण – कच्चे तेल रिजर्व के सॉवरेन स्ट्रेटिजिक भंडारण का निर्माण – चरण-I रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार का विस्तार” – ₹3999.75 लाख। (II) “Sovereign Strategic Storage of Crude Oil - Creation of Sovereign Strategic Crude Oil Reserve - Extension of Phase-I Strategic Petroleum Reserves” - ₹3999.75 lakhs.
-